राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

विषय :– इन्दिरा आवास योजना से सम्बन्धित आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस अनुभाग द्वारा क्रियान्विति कराई जा रही इन्दिरा आवास योजना से सम्बन्धित जारी आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें ताकि जिला स्तर पर प्रत्येक अधिकारी को योजना से सम्बन्धित जारी आदेश की जानकारी तत्काल प्राप्त हो सके। उक्त आदेशों को ग्रामीण आवासीय की श्रेणी में अपलोड किया जावें।

संलग्न :– आदेशों की प्रतियां।

(के.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)
परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.),
ग्रामीण विकास विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

अ. शा. टीप क्रमांकः पं. 27(31)ग्राविवि/ग्रुप–5/अपलोड/2014–15
जयपुर, दिनांक 18 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि :–
1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

U21/SE/R00/BS/13
8/2/13

ID. 227/Secy. R.D./2013
Dt. 7/2/13

F.No. – J-11014/2/2012-RH
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Rural Housing Division)

Krishi Bhawan, New Delhi- 110 001
Dated the 4th February, 2013

The Principal Secretary
Department of Rural Development
(All States/UT Administration (except Delhi and Chandigarh)

Subject : Revision of unit assistance provided to rural BPL households for construction of houses under Indira Awaas Yojana (IAY) and Homestead site

Sir/Madam,

Government has received Cabinet approval for enhancement of IAY unit assistance as well as homestead site cost. Revised unit assistance will be made available to IAY houses sanctioned on or after 1st April, 2013 and will remain in force till further orders. Accordingly, IAY guidelines will stand changed. Revised unit assistance and substitution to be made in IAY guidelines are indicated below. The said paragraphs in Indira Awaas Yojana (IAY) Guidelines may be substituted as follows :-

Item No.	Paragraph No.	Area	To be modified as
1.	Paragraph 3.1 (a)	Construction of House	Rs.70,000/- Rs.75,000/- in hilly/difficult areas including 82 LWE districts
2.	Paragraph 8.1 (vi)	Homestead sites	Financial assistance of Rs.20,000/- per beneficiary or actual, whichever is less, will be provided for purchase/acquisition of a homestead site of an area around 100-250 sq.mt.
3.	New paragraph to be added 3.1 (A)	Funds for administrative expenses	4% of funds for administrative expenses will be made available to state governments.

Expenses on item no. 1 and 3 (construction of house and funds for administrative expenses) to be shared by the Centre and States in the ratio of 75:25, in the case of North-eastern States 90:10 and in the case of UTs the central share will be 100%. Centre : State share on expenses for item no. 2 (homestead site) will be 50:50.

Government has also approved enhancement of unit assistance for construction of toilets to Rs.9,000/- under the Nirmal Bharat Abhiyan of the Ministry of Drinking Water and Sanitation. The beneficiaries of IAY are to be accorded priority.

Yours faithfully,

(Vijaya Srivastava)
Joint Secretary to the Govt. of Inddia
Tel. : 23386411

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ. 27(2)ग्राविवि/इ.आ./जीओआई/2013–14 जयपुर, दिनांक 23/24 जनवरी, 2014

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण क्षेत्रों में मैला ढोने के कार्य में लगे परिवारों को बसाने हेतु परियोजना तैयार कर प्रेषित करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना के जारी दिशा–निर्देश जून 2013 के बिन्दु संख्या 3.2.4 विशेष परियोजनाऐं में मैला ढोने वालो को बसाने की परियोजनाऐं सम्मिलित किया गया है। इस हेतु आई.ए.वाई. आवंटन की 5 प्रतिशत निधियां केन्द्रीय स्तर पर आरक्षित रखी गयी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के माध्यम से परियोजनाऐं पर्याप्त ब्यौरा और औचित्य दर्शाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करनी होगी। भारत सरकार की अधिकार प्राप्त समिति अनुमोदन के प्रयोजनार्थ इन पर विचार करेगी।

स्थानीय रूप से प्रासंगिक, पारदर्शी सामाजिक,–आर्थिक मानदण्डों को प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा कवरेज हेतु अन्य बसावटों को निर्धारित किया जाएगा तथापि ऐसी कुछ श्रेणी के पात्र लाभार्थी, जो ग्राम पंचायत के भीतर अलग–अलग स्थानों पर रह रहे हों, को शामिल करने के लिए अलग–अलग परिवार के दृष्टिकोण का प्रयोग किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का पालन करते समय पहली वरीयता मैला ढोने वाले व्यक्तियों के परिवारों को दी जायेगी जिनमें पुनर्वासित व्यक्ति भी शामिल होंगे।

अतः आपके जिले में सर्वे कराकर ऐसे गांवों की पहचान की जाये जहां मैला ढोने के कार्य में लोग कार्यरत है एवं उनको आवासीय सहायता का आवश्यकता है। उक्त क्रम में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उनको बसाने हेतु परियोजना तैयार कर शीघ्र प्रेषित की जावे ताकि राज्य स्तर से संकलित कर भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जा सके। उक्त परियोजना विभाग को माह 31.03.2014 तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

24/01/14

(हितबल्लभ शर्मा)
अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.)

(4)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ. 27(2)ग्राविवि/इ.आ./जीओआई/2013–14 जयपुर, दिनांक 24 जनवरी, 2014

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
राजस्थान।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु कार्य योजना तैयार करने बाबत्।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 समाप्ति की ओर है। आशा है लक्ष्यानुसार समस्त स्वीकृतियां जारी कर दी गई है। समस्त स्वीकृतियां जारी करने के उपरान्त शेष प्रतीक्षारत परिवारों की स्थिति आपके पास उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्रतीक्षारत परिवारों को लाभान्वित करने हेतु पूर्व तैयारी की जाये ताकि वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रारम्भ होने पर किसी प्रकार की असुविधा/अवरोध उत्पन्न नही हो। इस हेतु निम्न बिन्दु अनुसार कार्यवाही की जावें :–

1. इन्दिरा आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची की समीक्षा की जावे एवं वास्तविक पात्र प्रतीक्षारत परिवारों की स्थिति ग्राम पंचायतवार एवं पंचायत समितिवार तैयार की जावे। (संलग्न प्रपत्र के अनुसार)
2. समीक्षा उपरान्त इन्दिरा आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची के आधार पर शेष रहे प्रतीक्षारत लाभार्थियों की वर्गवार, ग्राम पंचायतवार एवं पंचायत समितिवार सूचना तैयार की जावे। आपसे प्राप्त सूचना के आधार पर भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्यों का वर्गवार आवंटन कराकर जिलेवार आंवटन निर्धारित कराया जावेगा।
3. वित्तीय वर्ष 2013–14 के आवंटित लक्ष्यानुसार माह मार्च, 2014 में पात्र प्रतीक्षारत परिवारों से वरीयतानुसार वर्ष 2014–15 में लाभान्वित करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर लिये जावे एवं उनका पंजीकरण आवाससॉफ्ट पर किया जाये।
4. बसावट या क्लस्टर दृष्टिकोण और अलग–अलग परिवार के दृष्टिकोण की आवश्यकताओं एवं लाभ के बीच संतुलन बनाते हुए इन्दिरा आवास योजना के लिए क्रियान्वित नीति तैयार की जानी है। सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से पीवीटीजी, वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी परिवार एवं स्थानीय रूप से प्रासंगिक, पारदर्शी सामाजिक–आर्थिक मानदण्डों को प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा कवरेज हेतु अन्य बसावटों हेतु पात्र परिवारों की पहचान कर उनको बसाने हेतु विस्तृत सर्वे कराकर परियोजना तैयार कर विभाग स्तर पर माह 30.3.2014 के प्रारम्भ में प्रेषित की जावे ताकि भारत सरकार स्तर की अधिकार प्राप्त समिति को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जा सके।

उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर निर्धारित समय सीमा में तैयार की गई परियोजनाओं को विभागीय स्तर पर प्रेषित काना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

24/01/14

(हितबल्लभ शर्मा)
अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.)

80

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(2) / ग्रावि–5 / इआ / जीओआई / पार्ट / 2013–14 जयपुर, दिनांक: 24 जनवरी, 2014

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र),
राजस्थान।

विषय :– इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की अलग से सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इन्दिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 3.6 के अनुसार रिलिज की गई निधियों की 4 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग योजना के संचालन के लिए किया जा सकता है, जिसमें से 0.5 प्रतिशत तक की राशि राज्य स्तर पर रखी जा सकती है। प्रशासनिक लागत के अन्तर्गत व्यय के लिए योग्य मदों में नियमानुसार व्यय किये जाने के निर्देश है।

अतः आप इन्दिरा आवास योजना के दिशा–निर्देश के पैरा 3.6 के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रशासनिक व्यय की अलग से सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

24/01/14

(हितबल्लभ शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(44)/ग्राविवि/ग्रुप–5/विविध/2013–14 जयपुर, दिनांक:२५जनवरी, 2014

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र),
राजस्थान।

विषय :– **Standard Operating Procedure (SOP) on Indira Awas Yojana** के क्रम में।

संदर्भ :– भारत सरकार के पत्र क्रमांक J-12025/1/2013 RH(A/c) दिनांक 7 जनवरी, 2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत गबन प्रकरण/दुःविनियोजन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये है। (प्रति संलग्न)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत गबन प्रकरण/दुःविनियोजन प्रकरणों का निस्तारण भारत सरकार द्वारा जारी **Standard Operating Procedure** के अनुसार कर विभाग को सूचित करने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

24/01/14
(हितबल्लभ शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्राविं)

No. J-12025/1/2013-RH (A/c)
Government of India
Ministry of Rural Development
....

D. No. 500 PS/RD&PR/201
DATE 15.1.14

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated, the 7th January, 2014

To

3703/SE/RD/HWS
16/1/14

(1) The Secretary (RD),
All States/UTs,
(2) The Secretary (Housing),
Andhra Pradesh and Karnataka

Subject: Standard Operating Procedure (SOP) for dealing with embezzlement/misappropriation of funds under IAY.

Sir,

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 25.11.2013 vide which a Draft Standard Operating Procedure (SOP) for dealing with embezzlement/misappropriation of funds under IAY was forwarded with the request to offer your comments/suggestions on the proposed SOP by 4th December, 2013 through e-mail. The draft SOP was also uploaded on the Ministry's website.

Three States, namely, Haryana, Rajasthan and West Bengal, have responded. The Government of Rajasthan has made some suggestions. These suggestions, to the extent found feasible, have been incorporated in the SOP.

A copy of the SOP as finalized is now enclosed for compliance and taking action while dealing with the cases of embezzlement/misappropriation of funds under IAY.

SE (Engg)
15/1/2014

Yours faithfully,

Encl: Copy of SOP

(B.C. Behera)
Deputy Secretary to the Govt. of India

Government of India
Ministry of Rural Development
(RH Division)

Standard Operating Procedure (SOP) for dealing with embezzlement/misappropriation of funds under IAY

Ministry of Rural Development receives a large number of complaints from Members of Parliament, other public representatives, NGOs and the general public regarding violation of Guidelines/embezzlement of funds, etc. for implementation of IAY. The complaints received in the Ministry are broadly on the following issues:

i. Non involvement of Gram Sabha in preparation of Five Year priority list/Annual select list.
ii. Tampering with Wait List/Five year priority list/Annual select list.
iii. Irregularities in selection of beneficiaries
iv. Delay in release of payment
v. Financial irregularities/misappropriation of funds/ embezzlement
vi. Imposing of unwarranted restriction on beneficiaries
vii. Social audit not being conducted
viii. Involvement of contractors

As the Schemes are implemented by respective State Governments/UT Administrations/DRDAs/ZPs, the action on complaints also primarily needs to be taken by them only. However, it has been observed that in many cases, State Governments/DRDAs/ZPs do not take timely remedial action. The Ministry of Rural Development has formulated a Standard Operating Procedure (SOP) for dealing with such complaints to ensure timely remedial/corrective action.

1. Grievances/Complaints

i) Petitions:

General/ non-specific representation relating to implementation of the Scheme and general observations/suggestions on the improvement in the Scheme will come under this category. These would include (1) inclusion of new names in List, (2) convergence with other programmes (3) general statement like corruption at all levels in the district/block/village etc.(4) Deprivation of eligible beneficiaries.

Action on references in the nature of petitions will be taken by RH Division in the Ministry in accordance with the provisions of the Scheme, guidelines and accepted policy of the Government and may not always be referred to the State Government unless required to do so.

ii) Grievances/Complaints regarding procedural violation of Guidelines:

Irregularities, which are born out of deficiencies like lack of capacity building, etc. will come under this category. These include allegations where no criminal intent is involved, such as delay in completion of houses, delay in inspection which results in delay in release of instalments.

Grievances/complaints on violation of Guidelines will be referred to respective State Government by the Ministry within 15 days of receipt. The State Govt will have the complaint enquired into by deputing a field Investigation team. The State Government will be required to send an Action Taken Report (ATR) within three months' of receipt of the complaint. The ATR should include the action taken on the current case and also the systemic changes that the State proposes to carry out so that such grievances do not recur.

iii) Complaints relating to effective implementation of the Scheme:

In this category, will be included complaints relating to large scale and prolonged deviation from the main provisions of the scheme including (1) non-involvement of Gram Sabha in the selection of beneficiaries, (2) not conducting Social Audits, (3) delay in releasing payment to beneficiaries(4) involvement of contractors etc.

Complaints relating to above and suggestions for effective implementation of the Scheme will be referred to the State Governments. In this case, the State Government will need to depute a senior officer or a team of officers from the Secretariat/Directorate to enquire into the matter and make specific actionable recommendations, which should be placed before the SLV&MC along with the views of the State Government The Field Investigation Report, the views of the State Government and the decision of the SLV&MC should also be conveyed to the Central Government as an ATR within three months of receiving the complaint from the Ministry.

iv) Complaints on financial irregularities:

(a) Any allegation relating to possible or actual loss to the exchequer and where criminal intent is involved will come under this category. These include (1)Tampering with wait list with intent of causing wrongful gain to another party, (2) embezzlement of funds/misappropriation of funds, unauthorized diversion, fudging of financial records, (3) Withholding release thereby deliberately inconveniencing beneficiary.

(b) The cases under **complaints on financial irregularities** will be referred to State Governments to furnish their views within 15 days. However, in case of serious nature of complaints, where criminal intent is involved and immediate action is necessitated and if the Division finds a prima facie case exists, then, a Central team with one officer of the Ministry (preferably Dir/DS level and above) or an Institutional National Level Monitor (NLM) will be deputed (within 15 days of receiving such complaint) for enquiring into the allegation(s) and submitting a field investigation report to the Ministry within a period of one month. In case matter is of grave concern central team along with an Institutional NLM will be deputed for enquiry into the matter and submitting a report within a period of one month. The field investigation report of NLMs/Central Team, after examination in the Ministry, will be immediately shared with the State Government and they shall submit the ATR to the Ministry within a period of 30 days.

(c) In case embezzlement/misappropriation of IAY fund is noticed during the course of inquiry by the Central Team or otherwise, the suspected embezzled/misappropriated amount will be immediately recouped to IAY Account by the concerned State Government and the fact of recouping the amount will be included in the ATR to be submitted by the State Government to the Ministry.

2. Extension of time for submission of ATRs

For any category of complaint, if the State Government fails to submit an ATR within the prescribed time period, the Ministry shall issue a reminder giving a grace period of another one month time with a caution that non submission of ATR will lead to stoppage of funds. If required, State Government can ask for reasonable additional time with justification. Consideration for providing additional time shall be undertaken by a Committee under the Chairmanship of Additional Secretary, comprising of the following officers as members from the Ministry:-

JS (SA)	- Member
Director/DS(Fin.)	- Member
Concerned Director/DS in the Division	- Convener

The Convener will prepare a gist of complaints along with the justification given by the State for seeking additional time. Based on the seriousness of the complaint and the explanation offered by the State, the Committee may decide to give additional time to the state for submitting the ATR.

3. Receipt and Review of Action Taken Report

The Committee referred to above will review the ATRs received from the States. The convenor will place before the committee, gist of the complaint, the ATR, findings of NLMs/Central Team if any and the action taken by the State thereon. The Committee will look into enquiry report and ATR and satisfy itself about appropriateness of the action taken on the complaints. The Committee may also invite the concerned State/district Officers physically or through video-conferencing, as may be decided by the Committee, to present its case before the

Committee, if need be, in case of category (iv) involving misappropriation/ embezzlement or financial irregularities.

4. Action expected from States for a satisfactory ATR:

In the case of complaints in category given in para 1 (ii) and 1 (iii), it is expected that the State Govt. would have issued necessary instructions/ guidelines to correct the deficiency observed. The Ministry may ask the State Government to intimate the effectiveness of the guidelines they issue. In addition, appropriate administrative action should be taken against those found to be violating the provisions of the guidelines.

With regard to the complaints relating to financial irregularities, generally, the following action should have been completed for an acceptable ATR:

For employees:

(i) Lodging FIR against the delinquent officer(s) in case, prima facie, a criminal intent is apparent and

(ii) Formal initiation of departmental enquiry

For elected officials:

(i) Proceedings for disqualification/ termination / recovery should have been initiated under the State PR Act and

(ii) Recovery should have been ordered by issue of a formal recovery certificate or a written order if, following a due process, recovery is due.

It is expected that proceedings initiated as above will progress to their logical conclusion with all due speed and progress. In this regard will also be reviewed by the Committee in the manner given in para 5. The Committee may seek periodic ATRs in these cases.

5. Consequences of not submitting satisfactory or timely ATRs

If the State fails to respond with a satisfactory ATR or within the specified time period, the Committee may recommend remedial action including stoppage of

further funding. Where the matter is of a serious nature, it could recommend CBI inquiry. Entrusting investigation to CBI would however require consent of the State Government concerned under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment (DPSE) Act, 1946. Hence, the State Government concerned would be requested to accord their consent on such proposed investigation under Section 6 of DPSE Act, 1946, within four weeks of issue of such request. The State Government can also initiate steps for getting a CBI inquiry done on its own behalf and keep the Ministry informed.

The decision of the Ministry on the ATR will be communicated to the State along with the course of remedial action to be taken by the State Government immediately. The State Government shall take appropriate action on the matter and submit to the Ministry the Compliance Report within three weeks. The Compliance Report received from the State Government will again be placed before the Committee. If the Committee feels that the action taken by the State is satisfactory, then the Committee may recommend for release of full amount due to the State/district. In case of unsatisfactory compliance of the recommendations, the Committee may continue to recommend curtailment or stoppage of funds till a satisfactory 'cure' is commenced.

In case ATRs are not received timely or are not satisfactory, an Institutional NLM(s) may be deputed with the approval of Secretary, Ministry of Rural Development to enquire into the matter and submit a report to the Ministry within a period of one month.

In case of a financial loss, if the committee is of the view that adequate progress is not being made to recover the loss and/or punish officials involved, the quantum of loss shall be treated as additional State liability in addition to the due share as per IAY scheme and will need to be deposited into the relevant account before release of the next instalment. In case of recovery of embezzled / misappropriated amounts or any part thereof, the same will be deposited in the IAY fund District level and will be treated as part of State share, in cases where State share for the ongoing financial year is still due. If there is no state share

due, then the deposited amount will be treated as State share for the next year given in advance.

6. Use of Awaasoft - MIS:

States may be familiar with the provisions for tracking complaints through AwaasSoft. As soon as a complaint is registered at Block level, it becomes possible to track it through the MIS. At all levels of implementation, States must ensure mandatorily registration and monitoring of complaints/grievances to ensure timely action and redressal.

7. Establishing Complaint Cells in States

(a) The State Governments should establish a Complaint Cell, under the direct charge of Secretary, Rural Development in the state, for looking into all the complaints related to IAY. The complaint cell may either be for complaints specifically related to IAY or it may be the same as for complaints related to other programmes/Schemes of Ministry of Rural Development.

(b) The State Governments should also appoint a nodal officer to inter-act with the Ministry of Rural Development on matters of complaints /embezzlement/ misappropriation of IAY funds.

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक– एफ–27(5) ग्रावि/ग्रुप–5/इंआयो/जिला/2014–15/पार्ट– जयपुर, दिनांक 12 मई, 2014

–: परिपत्र :–

ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के कियान्वयन हेतु जारी विभागीय परिपत्र क्रमांक –' एफ– 27 (5) ग्राविवि/इंआ/जिला/2013–14 जयपुर दिनांक 8 जुलाई, 2013 की निरन्तरता में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवासीय योजनाओं में आवास सॉफ्ट की अनिवार्यता लागू की है। जिला परिषद स्तर से समस्त स्वीकृतियां एवं राशि हस्तान्तरण आदि की कार्यवाही आवास सॉफ्ट के इन्द्राज के आधार पर ही किया जावे। स्वीकृति हेतु आवेदन–पत्र किश्त हस्तान्तरण हेतु प्रपत्र संख्या– 3, 4 व 5 पंचायत समिति स्तर पर ही संधारित रखे जावे। इन प्रपत्रों को जिला परिषद् पर मंगवा कर स्वीकृति व किश्त हस्तान्तरण की कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है।

इस प्रक्रिया से आवासों की स्वीकृति एवं किश्त हस्तान्तरण की कार्यवाही अविलम्ब की जा सकेगी। आवास सॉफ्ट पर स्वीकृति व किश्त हस्तान्तरण प्रपत्र का परीक्षण कर इन्द्राज कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विकास अधिकारी का होगा।

उक्त आदेश वित्तीय वर्ष 2011–12 से स्वीकृत आवासों पर लागू होंगे।

14/5/14

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान–जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान–जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्राविवि, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, जयपुर।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, ज्योति नगर, जयपुर।
8. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद् राजस्थान।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. वित्तीय सलाहकार, ग्राविवि/पंरावि, जयपुर।
11. समस्त जिला प्रभारी, ग्रावि एवं पंरावि, मुख्यालय, जयपुर।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
13. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
14. अधीक्षण अभियंता, ग्राविवि, जयपुर।
15. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (एम.एण्ड ई.) को परिपत्रविभागीय वेब–साईट पर अपलोड कराने के सम्बन्ध में।
16. परियोजना अधिकारी (अभि.)/अधि.अभियंता(आवास),ग्राविवि।
17. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजस्थान।

12/05/14
अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.)

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ. 27(5)ग्रावि–5/आईएवाई/जिला/2014–15 जयपुर, दिनांक 27 मई, 2014

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
राजस्थान।

विषयः– आवाससॉफ्ट पर इन्दिरा आवास योजना की सभी प्रविष्ठियां पूर्ण रूप से करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार स्तर पर इन्दिरा आवास योजना की समीक्षा गत दो वर्षों से आवाससॉफ्ट के माध्यम से की जा रही है। प्रायः यह देखने में आया है कि योजना से सम्बन्धित भौतिक एवं वित्तीय प्रविष्ठियां पूर्ण रूप से आवाससॉफ्ट पर इन्द्राज नहीं होने के कारण ऑनलाईन एमपीआर व आवाससॉफ्ट से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट में अन्तर आ जाता है। जिसके कारण राज्य की पूर्ण प्रगति भारत सरकार को दृष्टिगोचर नहीं हो पाती है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी समय–समय पर आपको निर्देशित किया जा चुका है।

भारत सरकार स्तर पर दिनांक 05–06 जून, 2014 को पीआरसी की बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें आवाससॉफ्ट द्वारा प्रदर्शित प्रगति व ऑनलाईन एमपीआर की प्रगति में अन्तर की समीक्षा की जाएगी।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आवासीय योजना से सम्बन्धित समस्त प्रविष्ठियां आवाससॉफ्ट पर अपडेट करने का श्रम करें ताकि समीक्षा के दौरान राज्य की वास्तविक स्थिति दृष्टिगोचर हो सके।

भवदीय

27/10

(हितबल्लभ शर्मा)
अधीक्षण अभियंता (ग्रावि)